



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतीपकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

C. Kaur
13.12.84

सं० 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 1984/अश्विन 20, 1906

No. 148]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 1984/ASVINA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1984

सार्दजनिक सूचना संख्या 112/7/84-एफ(आई)

सं. 103/11/83-एफ (आई) :—वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हर वर्ष घोषित भारत सरकार की आयात और निर्यात नीति के अनुसार, फीचर फिल्मों का आयात, उनका वितरण और मूल्य निर्धारण सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संबंधित नीति के अनुसार किया जाना होता है। तदनुसार, फीचर फिल्मों के आयात तथा आयातित फीचर फिल्मों के वितरण तथा उनके मूल्य निर्धारण संबंधी नीति, जो परिशिष्ट में दी गई है, एतद्-द्वारा अधिसूचित की जाती है।

विजय सिंह जाफा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

फीचर फिल्मों के आयात और आयातित फीचर फिल्मों के
वितरण और उनके मूल्य निर्धारण संबंधी नीति

1. लागू होना : यह नीति चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी किए गए चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में दत्ता परिभाषित फीचर फिल्मों (जिन्हें इनके बाद

“फिल्मों” कहा गया है), किन्तु वीडियो फिल्मों और शैक्षणिक फिल्मों के रूप में वर्गीकृत फिल्मों को छोड़कर आयात तथा आयातित फिल्मों के वितरण तथा उनके मूल्य निर्धारण पर लागू होगी।

2. फिल्मों का आयात :

2.1 पैरा 2.3, 2.4 और 2.5 में जो निर्दिष्ट है उसको छोड़कर फिल्मों का आयात केवल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (जिसे इसके बाद “निगम” कहा गया है), द्वारा ही किया जाएगा। यदि निगम के अलावा किसी अन्य एजेंसी को फिल्मों आयात करने की अनुमति दी जाती है तो भारत में फिल्मों आयात करने से पहले पैरा 2.3, 2.4 और 2.5 के उपबन्धों के अनुसार निगम को कैबिनेट/इजोशन संकेत दिया जाएगा।

2.2 निगम किसी भी वित्तीय वर्ष में उतनी विदेशी मुद्रा, जितनी इसे इस वित्तीय वर्ष के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निगम के परामर्श से मौजूद गई होगी, से अधिक खर्च करके फिल्मों का आयात नहीं करेगा। निगम फिल्मों का आयात या तो (1) परामर्श तरीके के आधार पर या (2) लाभ-महभाजन के आधार पर कर सकता है। फिल्म को लाभ-महभाजन के आधार पर आयात करने की दशा में विदेशी

निर्माता अधिकार धारक का हिस्सा किसी भी हालत में 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना। किन्तु फिल्म के लिए देश अधिकतम राशि 20,000 अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होगी। लाभ का विभाजन प्रिंट, भाड़े, बीमा, प्रचार, आदि और मीसा-शुल्क, वितरण कमीशन और सभी भारतीय करो पर हुए वास्तविक खर्चों को कम करके निवल बिल के आधार पर किया जाएगा।

2.3 विदेशी पाटी को फिल्मों का आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति इस प्रकार की पाटी के साथ भारत सरकार द्वारा या इसकी स्वीकृति से निगम द्वारा किए गए करार के अनुसरण में की जाएगी। जिन शर्तों के अन्तर्गत फिल्मों का आयात करने दिया जाएगा, उनको करार में निर्धारित किया जाएगा।

2.4 निगम और सरकारी भारतीय पाटी को भी उस फिल्मों का आयात करने के लिए अधिकृत कर सकता है जो भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, पाहों के प्रतियोगी हैं अथवा और प्रतियोगी, के फिल्म दाजूर में प्रविष्ट होती है, बशर्ते कि भारत को 15 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्मों के आयात पर विदेशी मुद्रा में कुल विदेशी मुद्रा की उस राशि से अधिक न हो जो एक प्रयोजन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श और उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर फिल्मों के आयात के लिए जारी किए जाएं, के अनुसार आवंटित की गई हो। इस प्रकार के मामलों में, आयात केवल सम्पूर्ण खरीद के आधार पर ही किया जाएगा। निगम को और सरकारी भारतीय पाटियों द्वारा लागत, बीसा और भुगतान के 15 प्रतिशत की दर से कैंनेलाइजेशन शुल्क दिया जाएगा। "लागत" में केवल प्रिंट और अन्य सामग्री की लागत भी शामिल होगी अर्थात् इसमें भारतीय खरीदार द्वारा विदेशी पाटी को दी गई रायल्टी भी शामिल होगी।

2.5 निगम अनिवासी भारतीय को भी उस फिल्म/उस फिल्मों का आयात करने की अनुमति दे सकता है जो उसके द्वारा भारत से बाहर या अधिकांशतया भारत से बाहर बनाई गई हो या जिसे के बारे में उसने स्वयं/द्वारा से वितरण के अधिकार प्राप्त किए हुए हों। यह अनुमति अनिवासी भारतीय द्वारा 10,000 अमेरिकी डालर की दर से कैंनेलाइजेशन शुल्क का अधिस में भरापान कर दिए जाने पर और इस धर्मा पर ही जायेगी कि यदि भारत, जहां अनिवासी भारतीय अमेरी मर्जी से फिल्म वितरित करता है, में फिल्म के निवल बिल का 15 प्रतिशत अथवा उस फिल्म को वितरण के लिए वितरक को देना जाता है, तो निगम द्वारा अनिवासी भारतीय को दी गयी राशि के 15 प्रतिशत 10,000 अमेरिकी डालर से अधिक हो जाता है तो 10,000 अमेरिकी डालर अथवा 15 प्रतिशत की दर से कैंनेलाइजेशन शुल्क की दर से भारत में दिया जाएगा अर्थात् इस धंड के अन्तर्गत फिल्मों के आयात की दशा में विदेशी मुद्रा में कुल देश में जायदा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस धंड के अन्तर्गत निगम द्वारा जिन फिल्मों के आयात की अनुमति दी जायेगी उनका आयात सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा फिल्मों की गुणवत्ता के बारे में समत-संगत पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत होगा।

नोट:—इस सम्म के प्रयोजन हेतु किसी फिल्म की अधिकांशतया भारत से बाहर बनाई गई फिल्म तब समझा जायेगा जब प्रदर्शित

किए जाने वाले 50 प्रतिशत अंश की शूटिंग भारत के बाहर की गई हो।

3. आयातित फिल्मों का वितरण:

3.1 निगम द्वारा आयातित फिल्मों का वितरण या तो निगम द्वारा स्वयं या निजी सुस्थापित वितरकों के माध्यम से किया जा सकता है। आयातित फिल्मों का वितरण निजी सुस्थापित वितरकों के माध्यम से करने की शर्तें वे होंगी जो निगम और वितरकों द्वारा आपस में तय की जाएं।

3.2 भारत सरकार या निगम तथा किसी विदेशी पाटी के बीच हुए करारों के मामले में, आयातित फिल्मों का वितरण करार की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

3.3 और सरकारी भारतीय पाटी या अनिवासी भारतीय आयातित फिल्मों का भारत में वितरण करने की अपनी व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. मूल्य निर्धारण:

फिल्म का मूल्य अर्थात् किसी फिल्म के लिये रायल्टी तथा प्रिंटों और फिल्म से संबंधित अन्य सामग्री के लिए किया जाने वाला भुगतान, विदेशी पाटियों तथा निगम सहित आयातकों द्वारा सीधे तय किया जायेगा। तथापि, जहां निगम का यह मत हो कि विदेशी पाटी तथा भारतीय और सरकारी पाटी के बीच तय किया गया फिल्म का मूल्य या भारतीय वितरक द्वारा अनिवासी भारतीय को उपयोग और प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला मूल्य उचित नहीं है तो वह स्वयं अपना अधिकतम कर सकेगा और संबंधित पाटियों द्वारा दिए जाने वाले कैंनेलाइजेशन शुल्क का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मूल्य तय कर सकेगा।

5. अषवाद:

इस नीति में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय लिखित करणों के आधार पर इस नीति की किसी भी अपेक्षा को हटा सकेगा या उसके किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा या उस में संशोधन कर सकेगा।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 12th October, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 112/7/84-F(I)

No. 103/11/83—F(I).—According to the Import and Export Policy of the Government of India announced by the Ministry of Commerce every year, import of feature films, their distribution and pricing is to be made as per the connected policy of the Government in the Ministry of Information and Broadcasting. Accordingly, the policy for import of feature films and distribution and pricing of imported feature films as given in the Annexure, is hereby notified.

VIJENDRA SINGH JAIN, Jt. Secy.

ANNEXURE

POLICY FOR IMPORT OF FEATURE FILMS AND DISTRIBUTION AND PRICING OF IMPORTED FEATURE FILMS

1. Applicability.—This Policy is applicable to the import of feature films (hereinafter referred to as

"films") as defined in the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 issued under Section 8 of the Cinematograph Act, 1952 but excluding video films and films categorized as educational films and to the distribution and pricing of imported feature films.

2. Import of films:

2.1 Films shall be imported only by the National Film Development Corporation (hereinafter referred to as "the Corporation") except as indicated in paragraphs 2.3, 2.4 and 2.5. Even where agencies other than the Corporation are permitted to import films, the Corporation shall be paid canalisation fees as per provisions of paragraphs 2.3, 2.4 and 2.5 before the films are imported into India.

2.2 The Corporation shall not import films in any financial year by spending foreign exchange in excess of the amount placed at its disposal by the Ministry of Information and Broadcasting in consultation with the Department of Economic Affairs for that financial year. Films can be imported by the Corporation either (a) on outright purchase basis or (b) on profit-sharing basis. In case a film is imported on profit-sharing basis, the share of the foreign producer/right holder shall, in no case, exceed 60 per cent, subject to the condition that the maximum amount payable for a film would not exceed US \$ 25,000. The profit will be shared on the basis of the net billings, after deducting the actual expenses on cost of print, freight, insurance, publicity, and custom duty, distribution commission and all Indian taxes.

2.3 Imports can be permitted to be made by a foreign party in pursuance of an agreement entered into by the Government or, with their approval, by the Corporation, with such party. The conditions under which the films shall be allowed to be imported shall be laid down in the agreement.

2.4 A Private Indian Party can also be authorised by the Corporation to import films which are entered in the film market of the International Film Festivals of India, whether competitive or non-competitive, subject to the condition that the total foreign exchange outflow on import of films at one International Film Festival of India does not exceed the amount of foreign exchange allocated for the purpose by the Ministry of Information and Broadcasting in consultation with the Department of Economic Affairs and in accordance with the guidelines that may be issued by the Ministry of Information and Broadcasting for the import of films on the occasion of the International Film Festivals of India. Imports in such cases shall be allowed on outright purchase basis only. The Corporation shall be paid by the private Indian parties canalisation fee at the rate of 15 per cent of the c.i.f., the "cost" element in c.i.f. consisting of not only the cost of print and other material but also of the royalty paid by the Indian buyer to the foreign party.

2.5 A non-Resident Indian may also be permitted by the Corporation to import a film either produced by him outside India or mainly outside India or a film in respect of which he has acquired proprietary distribution rights for India on payment of canalisation

fee at the rate of US \$ 10,000 per film to be paid by the Non-Resident Indian in advance and subject to the condition that in case 15 per cent of the net billings of the film in India where the Non-Resident Indian distributes the film on his own account or 15 per cent of the amount paid to the Non-Resident Indian by a distributor where the film is sold for distribution to a distributor exceeds the equivalent of US \$ 10,000 of the difference between U.S. \$ 10,000 and 15 per cent of the amount of net billing or the amount paid to the distributor as the case may be shall be paid as additional canalisation fee, in Indian rupees, to the Corporation and that no repatriation of funds in foreign exchange shall be allowed in the case of import of films under this clause. The import of films allowed by the Corporation under this clause shall be in accordance with the guidelines, regarding quality of films, issued by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time.

(Note : For the purpose of this clause, a film shall be deemed to be produced mainly outside India if more than fifty per cent footage to be displayed has been shot outside India).

Distribution of imported films:

3.1 The film imported by the Corporation can be distributed by them either on their own account or through private established distributors. The terms and conditions for distribution of imported films through the private established distributors shall be such as may be mutually settled between the Corporation and the distributors.

3.2 In the case of agreements entered into between the Government of India or the Corporation and a foreign party, distribution of imported films shall be made in accordance with the terms of the agreement.

3.3 A private Indian party or a non-resident Indian shall be free to make his own arrangements for distribution of imported films in India.

4. Pricing.—The price of a film i.e. the royalty for a film and payment to be made for prints and other material regarding the film shall be settled by the foreign parties and the importers, including the Corporation, direct. However, where the Corporation is of the opinion that the price of a film which has been settled between a foreign party and an Indian private party or the price to be paid by an Indian distributor to a Non-Resident Indian for exploitation and exhibition is not reasonable, they can make their own assessment and arrive at a price for the purpose of determining the canalisation fees to be paid by the parties concerned.

5. Exceptions.—Notwithstanding anything contained in this Policy, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting may waive any of the requirements or relax or modify any of the provisions of this Policy for reasons to be recorded in writing.

